

V8. 14175
16/6/04

भारत सरकार मुद्रांक १८-१७१५
दे दिनांक... २१.५.०४

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-३३००४/९९

REGD. NO. D. L. 33004/99

प्रकाशित दिनांक ०४



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 400
K.P. 30
Dept. 150
C.B. 220

सं. 155]
No. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2004/चैत्र 6, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2004/CHAITRA 6, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2004

पूरा किया

प्रभारी
रा० वि० एकक

सा.का.नि. 222(अ)—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मुम्बई पत्तन न्यास (आवासों का आवंटन और अभिग्रहण) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (निवासों का आवंटन और अभिग्रहण) विनियम, 1975
महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 39) की धारा 28 के अंतर्गत प्रदान किये अधिकारों के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 124 की आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से मुंबई पत्तन का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है. आगे मुंपोट्ट कर्मचारी (निवासों का आवंटन और अभिग्रहण) विनियम 1975 में निम्न संशोधन होंगे -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

(1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (निवासों का आवंटन और अभिग्रहण) संशोधन विनियम 2004 कहलाये जाय.

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे.

2. मुंपोट्ट कर्मचारी (निवासों का आबंटन और अभिग्रहण) विनियम 1975 में

(i) विनियम 3 के खण्ड (जी) के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए -
"किराया" का अर्थ है, इन विनियमों के अंतर्गत आबंटित आवास के लिए विनियम 11, 12 और 13 के अनुसार प्रतिमाह देय राशि.

(ii) विनियम 12 के बदले निम्न का समावेश किया जाय -

12 (1). जब आबंटन प्रत्येक कर्मचारी को साझेदारी में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप में किया जाता है, ऐसे सारे कर्मचारी नीचे उप विनियम (2) और (3) में दिये गए के अनुसार किराया अदा करेंगे. जहाँ पर आवास एक साझेदार के रूप में दिया जाता है अथवा संयुक्त रूप से आबंटित किया जाता है, वहाँ विनियम 13 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किराया वसूल किया जाएगा. कर्मचारी उनके व्यक्तिगत आवास में इस्तेमाल की गई बिजली के बिलों का भी भुगतान करेंगे.

परन्तु आवास के संबंध में मंडल द्वारा देय नगर और अन्य कर अथवा मकान के लिए दी विशिष्ट सेवाओं - पानी, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक लिफ्ट्स के लिए आवश्यक उर्जा आदि जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिकर नहीं भरेंगे. जो कर्मचारी निःशुल्क आवासों के ग्राही हैं, या ऐसे पदों पर तैनात हैं, जिनकी सेवा शर्तों में निःशुल्क आवास प्रदान करने की भी एक शर्त शामिल है वे जब तक ऐसे आवासों में रहते हैं, तब तक उक्त सेवाशर्तें लागू रहने तक उन रियायतों का लाभ उठा सकते हैं.

2. मंडल के सभी कर्मचारी, जब तक इन विनियमों में स्पष्टरूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, आवासों का मानक किराया अदा करेंगे, जो, सरकार द्वारा समय-समय पर एफआर 45 ए के अंतर्गत जारी किये अनुदेशों के अनुसार, निवास क्षेत्र आधारपर, लायसेंस-शुल्क के फ्लैट दर के समान है.

3. अव-सामान्य आवास के किराये की वसूली के संबंध में ये वसूली ऐसी न्यूनतम या नाम-मात्र दरों से की जाएगी, जो मण्डल ने आवास की अवसामान्यता का स्तर देखते हुए एवं स्थान की श्रेणी, उपलब्ध कराई गई सेवाएँ, आवास की स्थिति एवं स्वरूप आदि जैसे घटकों के आधारपर नियत की हो.

4. मंडल को यह अधिकार है कि वह, किराये की वसूली की दरों में किसी भी समय संशोधन कर सकता है.

(iii) विनियम 13 के स्थानपर निम्नलिखित पढ़ा जाए —

13. प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब आवासों में साझेदारी में अथवा संयुक्त रूप में रहने की अनुमति दी गई हो, तो किराये की वसूली निम्नप्रकार होगी —

- (1). जब दो या दो से अधिक कर्मचारियों को उसी आवास में साझेदारी से रहने की अनुमति दी जाती है तब नियतभागी को विनियम 12 के उप विनियम (2) और (3) के अधीन उसके द्वारा देय राशि के अनुसार भुगतान करना होगा जब तक वह किराया मुक्त निवास का हकदार नहीं होता और ऐसे नियतभागी को साझेदार अथवा साझेदारों से अनुपातिक किराया वसूल करने की व्यवस्था करनी होगी.
- (2). जब दो या दो से अधिक कर्मचारियों को एक ही आवास संयुक्त रूप से आबंटित किया जाता है तब विनियम 12 के उप-विनियम (2) और (3) के अधीन देय राशि के अनुसार उनके बीच अनुपातिक किराया का भुगतान करना होगा.

iv) विनियम 16 के स्थानपर निम्नलिखित का समावेश किया जाए -

16. मकान किराया भत्ता निम्नलिखित को प्रदान नहीं किया जाएगा.

- (i) ऐसे कर्मचारी का जिसे आवास आबंटित किया गया है.
- (ii) ऐसे कर्मचारी/कर्मचारियों को जो नियमभागी के साथ आवास में साझेदारी कर रहा है/कर रहे हैं.
- (iii) ऐसा कर्मचारी जिसका पति/जिसकी पत्नी को आवास आबंटित किया है और
- (iv) दो या उससे अधिक कर्मचारियों को एक ही आवास संयुक्त रूप से आबंटित किया जाता है.

[मिसिल सं. एच-11011/2/94-पीई-1]

टिप्पणी :-

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

1. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आवासों का आबंटन और अभिग्रहण) विनियम का मुख्य विनियम सरकार द्वारा दिनांक 20.8.1975 के पत्र क्र.पीईबी-12/75 के अंतर्गत मंजूर किया गया था. महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 की उपधारा (I) की

आवश्यकतानुसार सरकार का अनुमोदन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था.

2. प्रथम संशोधन सरकार द्वारा दिनांक 7.3.78 के पत्र क्र.पीईबी - 85/77 के अंतर्गत मंजूर किया गया और इसे दिनांक 9.3.1978 के जीएसआर क्र.163(ई) के रूप में ~~अनुमोदित~~ राजपत्र में प्रकाशित किया गया.
3. अगला संशोधन दिनांक 22.8.1996 के जीएसआर क्र.377(ई) के रूप में भारत ~~के~~ राजपत्र में प्रकाशित किया गया.
4. पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) के दिनांक 16.2.1999 के पत्र क्र. एच-11011/2/94/पीई-II की सूचनानुसार अंतिम संशोधन दि.16.2.1999 के भारत ~~के~~ राजपत्र में प्रकाशित किया गया.

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2004

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees (Allotment and Occupancy of Residence) Amendment Regulations, 2004 made by the Board of Trustees of Mumbai Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

**Mumbai Port Trust Employees
(Allotment & Occupancy of
Residences) Regulations, 1975.**

In Exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mumbai with the approval of the Central Government as required under Section 124 of the said Act, hereby make the following regulations further to amend the Mumbai Port Trust Employees (Allotment and Occupancy of Residences) Regulations, 1975, namely :-

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Mumbai Port Trust Employees (Allotment and Occupancy of Residences) Amendment Regulations, 2004.
- (2) They shall come into force from the date of notification in the official Gazette.

2. In the Mumbai Port Trust Employees (Allotment and Occupancy of Residences) Regulations, 1975.

- (i) For existing Clause (g) of Regulation 3, the following shall be substituted :-

“rent” means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of regulations 11, 12 and 13 in respect of a residence allotted under these regulations.”

- (ii) Regulation 12 shall be substituted by the following :-

“12(1) All employees to whom residences are allotted shall pay rent as provided in sub regulations (2) and (3) below, when allotment has been made to an individual employee and the residences are not shared. Where a residence is shared or joint allotment is made, rent shall be recovered as provided in regulation 13. The employees shall also pay the cost of electricity consumed by their individual residence, but not the municipal and other taxes payable by the Board in respect of the residence or compensation in respect of other specific services such as water, conservancy, common lighting, energy consumed by electric lifts, etc., provided for the residence. Provided that such employees as are in occupation of residences on a rent free basis and the holders of posts to which rent free residences are attached as a condition of service shall continue to enjoy the concession so long as they continue to be in occupation of those residences and/or the relevant condition of service continues to be applicable.

- (2) All the employees of the Board, shall unless otherwise expressly provided in these regulations, pay standard rent for quarters which is equivalent to flat rate of licence fees on living area basis as per Government instructions issued from time to time under FR 45A

- (3) The recovery of rent for sub-standard residence shall be at such reduced or nominal rates as may be fixed by the Board having regard to the extent of sub-standardness of the residence depending on the scale of accommodation, amenities provided, nature and condition of the residence and such other factors.
- (4) The Board shall reserve the right to revise the rates of recovery of rent at any time."
- (iii) Regulation 13 shall be substituted by the following :-
- "13. Rent shall be recovered as follows when residences are allowed to be shared or joint allotment is made by the Administrative Authority.
- (1) when two or more employees are allowed to share the same residence, the allottee, unless he is entitled to rent free accommodation, shall pay as payable by him under sub regulations (2) and (3) of regulation 12 and it shall be for such allottee to make arrangements to recover proportionate rent from the sharer or sharers;
- (2) when two or more employees are jointly allotted the same residence they shall between them pay proportionate rent as payable under sub regulations (2) and (3) of Regulation 12."
- (iv) Regulation 16 shall be substituted by the following :-
- "16. No House Rent Allowance shall be granted to -
- (i) An employee to whom a residence is allotted;
- (ii) An employee/s who is/are sharing the residence alongwith the allottee;
- (iii) An employee whose spouse is an employee to whom a residence is allotted; and
- (iv) Two or more employees when they are jointly allotted the same residence."

[F. No. H-11011/2/94-PE-1]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

Foot Note :-

1. Principal Regulations of MbPT Employees (Allotment and Occupancy of Residences) Regulations were sanctioned by the Government under letter No.PEB-12/75 dated 20.8.1975. Government's approval was published in the official Gazette as required under Sub-Section (i) of Section 124 of MbPT Act, 1963.
2. First amendment was sanctioned by the Government under letter No.PEB-85/77 dated 7.3.1978 and was published in the Gazette of India as GSR No.163(E) dated 9.3.1978.
3. Second last amendment was published in the Gazette of India dated 22.8.1996 as GSR No.377(E) dated 22.8.1996.
4. Last amendment was published in the Gazette of India dated 16.2.1999 as conveyed by MOST (PW) letter No.H-11011/2/94/PE-II dated 16.2.1999.